THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI SUKH RAM): (a) and (b) The project for agricultural planning based on Agro-Climate Regions was launched in June, 1988 with the setting up of 15 Zonal Planning Teams one for each of the identified agro-climatic regions. So far three major phases of this project have been completed;

(i) preparation of zonal profile and strategy for 15 broad agro-climatic zones;

(ii) Preparation of indicative State Plans disaggregated by agro-climatic sub-regions (87 sub-regions for the country as a whole), incorporating profiles, priorities and programmes covering land and water resources development, crop husbandry, development of allied agriculture sector, etc.;

(iii) Extension of Agro-climatic Regional Planning Project (ACRP) to district/sub district planning by way of providing technical inputs to the decentralised planning process on subjects of agro-climatic planning relevance. The work has been carried out/in progress in 33 selected districts covering major agro-climatic and inatitut-tional situations.

An implementation plan on axperi-mental basis for selected projects/ programmes among the selected districts of agro-climatic relevance is proposed. Agro-climatic Regional Plan ning Project has already been incorporated into Eighth Five Year Plan.

(e) Docs not arise,

योजना प्रक्रिया में परिवर्तनों के लिए सुझाव

2632. **मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी :** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान किन-किन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने योजना प्रक्रिया में परिवर्तन/संशोधन करने के लिए सुझाव दिए हैं;

(ख) इन सुझावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या इस संबंध में सरकार के विचाराधीन कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) से (ङ) राज्यों के मुख्य मंत्री समय-समय पर अधिकांशत: राष्ट्रीय विकास परिषद में विचार-विमर्श के दौरान आयोजना प्रक्रिया एवं संबंधित मामलों में परिवर्तन संबंधी सुझाव देते रहते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की हाल ही की बैठक में इस सबंध में व्यक्त किए गए विचार निम्नानुसार है :—

(क) आर्थिक नीति योजना तैयारी आदि महत्वपूर्ण मामलों पर राज्यों से और अधिक विचार-विमर्श। इस प्रस्ताव में अन्य बातों के साथ-साथ योजना आयोग ढांचे में राज्य के मुख्य मंत्रियों की भागीदारी शामिल है।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र योजना में राज्यों के लिए बड़ा हिस्सा।

(ग) आयोजना प्रक्रिया में व्यापक भागीदारी लोगों की भागीदारी तथा स्वैच्छिक संगठनों को महती भूमिका के सुसाध्य बनाने के लिए प्रभावी विकेन्द्रीकरण यह सुझाया गया है कि आयोजना प्रक्रिया को वित्तीय प्रशासनिक तथा राजकोषीय अधिकारों के प्रत्यायोजन के साथ जिले तथा पंचायत स्तर पर विकेन्द्रीकरण किया जाना चाहिए।

(घ) बदलती परिस्थितियों के अनुसार समायोजन करने में सक्षम बनाने तथा क्षेत्रीय एवं स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार स्कीमों/कार्यक्रमों की अभिकल्पना तथा क्रियान्वयन हेतु राज्यों द्वारा अपनाए जा रहे नवीन प्रकार के उपायों के लिए और अधिक छूट देना।

(ङ) कार्यदल संबंधी विचार-विमर्श क्षेत्रकीय परिव्ययों को अंतिम रूप देने के तरीके केन्द्रीय सहायता का निर्धारण जारी करने आदि सहित राज्य योजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए प्रक्रिया की पुनरीक्षा करना।

(च) मामले के "विकासात्मक" स्वरूप पर जोर देने के लिए "योजना तथा "गैर-योजना" के तहत व्यय के वर्गीकरण का संशोधन।

(छ) पर्यावरण तथा अन्य स्वीकृतियों के लिए "एकल खिड़की प्रणाली" की स्थापना के जरिए राज्य परियोजनाओं की तेजी से स्वीकृति।

राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में ऐसे सभी सुझावों पर विस्तार से चर्चा की जाती है जहां पर आम सहमति पर पहुंचने का प्रयास किया जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद के विचार-विमर्श में एक सीमा तक लचीलापन लाने तथा आयोजना प्रक्रिया में लगातार उपयुक्त परिवर्तन लाने में सहायक रहे हैं। दिशात्मक आयोजना पर आ 'धित आठवीं योजना भी ऐसे परामर्श का परिणाम है। आयोजित आर्थिक विकास की प्रक्रिया में राज्यों को हमेशा भागीदारों के रूप में माना गया है। योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए केन्द्र तथा राज्यों के संयुक्त उत्तरदायित्व पर सदा जोर दिया गया है।]

Implementation of Task Force Report on ISS Officers

2633. SHRI IQBAL SINGH; Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION foe pleased to state:

(a) Whether it is a fact that Department of Statistics had some time back appointed a Task Force to look into the career aspirations of ISS Officers;

(b) if so, when the Task Force sub. mitted its report;

(c) whether Government have take any action on it; and

(d) by when Government propose to implement the suggestions made in the said report?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI SUKH RAM): (a) and (b) A Task force was set up on 28-11-1990 to consider the aspect of Cadre Review of the ISS in all its perspectives. The Task Force submitted a draft report on 15-5-1991.

(c) and (d) The process of consultation with different Departments of the proposals in the report was set in motion. In the meanwhile, in the light of instructions in the context of the efforts for reduction of posts to reduce administrative expenditure, the ongoing cadre review was deferred for the time being. However, the possibility of encadering certain indi-